आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, बुधवार 22 जुलाई 2026
■ वर्ष : 5 ■ अंक : 228
■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2
dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

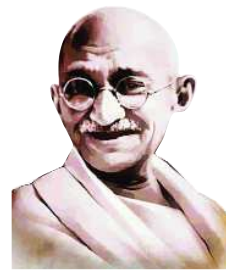

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

नामांतरण घोटाले में गाज राजस्व उपायुक्त हटाए गए

पेज-2

जिम्बाब्वे दौरे को युवा टीम इंडिया तैयार

पेज-5

पशु मुक्त देपालपुर में फिर दिखने लगी गाये

पेज-6

बूथ जीतो, चुनाव जीतो...

कांग्रेस ने शुरू किया मिशन बूथ

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • चुनाव आते ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा जिस कमी का अहसास होता है, अब पार्टी उसी कमजोरी को दूर करने में जुट गई है। नेताओं की बैठकों और बड़े आयोजनों से आगे बढ़कर कांग्रेस ने अब अपना पूरा फोकस बूथ की राजनीति पर कर दिया है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को पार्टी ने संगठन की जमीनी ताकत परखने का मौका मानते हुए हर बूथ पर अपना नेटवर्क खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है।

शहर कांग्रेस ने तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर एक अध्यक्ष, एक बूथ प्रभारी और एक महिला प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। खास बात यह है कि कमेटियां गठित करने के बाद मामला सिर्फ नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस के बड़े नेता इन पदाधिकारियों से सीधे संपर्क करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनके घर तक पहुंचकर बूथ की वास्तविक स्थिति जानेंगे।

दरअसल, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि चुनाव के दौरान पार्टी का संगठन कागजों और बैठकों में तो सक्रिय दिखाई देता है, लेकिन मतदान केंद्र तक पहुंचते-पहुंचते उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। भाजपा के मुकाबले बूथ मैनेजमेंट में पिछड़ना कांग्रेस के लिए लगातार चिंता का विषय रहा है। अब पार्टी इसी अंतर को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी बूथ कमेटियों को प्राथमिकता देते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 में खुद बैठकों की कमान संभाल ली है। बैठक में बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जाएगा।

कांग्रेस ने इस बार बूथ कमेटियों में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की रणनीति बनाई है। प्रत्येक बूथ पर महिला प्रभारी की नियुक्ति के पीछे पार्टी की कोशिश महिला मतदाताओं से सीधा संपर्क बढ़ाने की है। इसके अलावा वार्ड स्तर के पदाधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने में सबसे बड़ी अड़चन क्या है।

नगरीय चुनाव होगा 'टेस्ट मैच', नजर 2028 पर

कांग्रेस की इस पूरी कवायद को सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव तक सीमित नहीं माना जा रहा है। पार्टी बूथ कमेटियों के जरिए ऐसा संगठनात्मक नेटवर्क तैयार करना चाहती है, जो 2028 के विधानसभा चुनाव तक लगातार सक्रिय रहे। यानी निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए बूथ मैनेजमेंट का टेस्ट होंगे और इसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब चुनौती सिर्फ कमेटियां बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें चुनाव तक सक्रिय रखने की है। कांग्रेस अगर इस बार बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने में सफल होती है तो आने वाले चुनावों में उसे इसका फायदा मिल सकता है। वरना पहले की तरह कागजों पर मजबूत संगठन और मतदान केंद्र पर कमजोर पकड़ का सवाल फिर खड़ा होगा।

इनका कहना है...

कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी अब बूथ प्रभारी, बूथ समिति और पन्ना प्रभारी की व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करेगी।

– **चिंटू चौकसे,**
शहर कांग्रेस अध्यक्ष

संगठन सृजन के तहत पार्टी अब अपनी कोर ईकाई को मजबूत करने के लिए अब बूथ प्रबंधन को लेकर ब्यूह रचना बनाई जा रही है। इसका फायदा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी संगठन को मिलेगा।

– **अमित चौरसिया,**
प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

दतिया के फार्मूले ने देपालपुर में उड़ाई नेताओं की नींद

सोशल मीडिया पर नेताओं के समर्थकों ने चलाए शब्दों के बाण

देपालपुर • दैनिक इंदौर संकेत

दतिया उपचुनाव में भाजपा ने एक नया फार्मूला अपनाया है। 35 साल से जमे भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद कई नेता, विधायक, पूर्व विधायक सकते में आ गए। इसका नजारा देपालपुर में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लिखा गया दतिया का फार्मूला अब देपालपुर में भी लागू होगा। यह निशाना विधायक पर लगाया गया। उसके बाद विधायक समर्थक भी सोशल मीडिया पर अपने नेता के लिए लिखते नजर आए, टिकट तो हमारी जेब में है। इतना ही नहीं कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व विधायक के समर्थक भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। दतिया तो केवल एक इशारा देपालपुर अभी बाकी है। लगातार एक दूसरे के समर्थक सोशल मीडिया पर तीखे हमले करते हुए देखे गए। भाजपा के इस फॉर्मूले ने कहीं नेताओं की नींद हराम कर दी है। दतिया फार्मूले से प्रदेशभर के नेता टेंशन में है। यह बीजेपी है कुछ भी कर सकती है, घर बैठे आदमी को कब विधायक, सांसद बना दे, कुछ कह नहीं जा सकते। जो नेता क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे, उन्होंने भी जाना-आना चालू कर दिया। भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगठन भाजपा के लिए सर्वप्रथम है। संगठन के खिलाफ जो जाएगा, उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी, भाजपा के लिए चुनौती होगा। एक-एक विधानसभा में तीन-तीन दावेदार को मैनेजमेंट करना, अगर देपालपुर की बात करें तो वर्तमान विधायक मनोज पटेल, पूर्व विधायक विशाल पटेल, हिंदूवादी नेता राजेंद्र चौधरी जैसे दावेदार शामिल है। लेकिन विधानसभा चुनाव को 2 साल से अधिक समय बाकी है, उसके बावजूद भी नेताओं ने अभी से मैदान पकड़ लिया और उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर आमने-सामने हो रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि नेताओं में टिकट को लेकर कितनी बेचैनी है।

न्यूज ब्रीफ

- जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन बंद
- ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है इसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नही है : प्रियंका गांधी
- लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी बीजेपी
- दिल्ली में CJP प्रदर्शन को लेकर अब तक कुल 10 FIR दर्ज
- लगातार बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा रोकी गई
- यूपी भाजपा आज प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन आयोजित करेगी
- सिक्किम लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हुआ, 5 फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी
- अयोध्या : चढ़ावा गणना से जुड़े पुराने सभी 36 कर्मियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त की गई
- ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने किए हमले, CENTCOM ने दी जानकारी
- महाराष्ट्र सरकार आज मनाएगी NCP के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष अजीत पवार की जयंती
- आज UP बीजेपी का बूथ-स्तरीय सम्मेलन

डीएवीवी ने ऑनलाइन मूल्यांकन टाला

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर चिंताओं के कारण अपने महत्वाकांक्षी ऑनलाइन आंसर शीट मूल्यांकन प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किए गए ऑनलाइन मूल्यांकन सिस्टम में गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना पड़ा। डीएवीवी ने अप्रैल से ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी और प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी चिंताओं के कारण इसे लागू करने में देरी हुई। अलग-अलग एजेंसियों की प्रेजेंटेशन की समीक्षा करने के बाद, यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद की एक कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया था। हालांकि, मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित सिस्टम के कुछ तकनीकी पहलुओं पर चिंता जताई। यूनिवर्सिटी द्वारा बताई गई मुख्य समस्याओं में से एक आंसर शीट को स्कैन करने की प्रक्रिया है। प्रेजेंटेशन के दौरान, एजेंसी ने स्कैनिंग के लिए आंसर बुक के पन्नों को अलग करने और बाद में उन्हें फिर से जोड़ने का सुझाव दिया।

किताबों में बदला इतिहास, जोड़े नए अध्याय बना धर्मेंद्र प्रधान को न हटाने की वजह

भुवनेश्वर (एजेंसी) • दिल्ली में जंतरमंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दें। सीजेपी के संसद मार्च के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे।

पांचवीं और अहम बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान कोई आयातित नेता नहीं है। वे एबीवीपी से बीजेपी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। अगर उनका इस्तीफा होता है तो पीएम मोदी के अब तक कार्यकाल में पहली बार विपक्ष या कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने वाले दलों को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है अगर धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय चेंज हुआ या इस्तीफा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एबीवीपी, बीजेपी और पीएम मोदी के लिए असहज स्थिति का निर्माण होगा। इसके अलावा एक और दलील दी जा रही है कि उन्होंने पाठ्यक्रम में जिस तरह से आरएसएस की मर्जी के अनकूल बदलाव किए हैं, वह भी उनके विरोध का एक बड़ा कारण है। अब मुगल शासक 'अकबर द ग्रेट' पाठ्यक्रम में नहीं है बल्कि आपातकाल पढ़ाया जा रहा है।

इस्तीफा नहीं होने के यह कारण

अब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच पेपर लीक के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा है लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उनका इस्तीफा होगा। इसकी बड़ी वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में क्रेडिबिलिटी की कमी और जोश अधिक है। सरकार को अपने आंकलन में उतना कोई बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। मॉनसून सत्र जरूर चल रहा है लेकिन कोई चुनाव सिर पर नहीं है। तीसरी बात यह है कि पीएम मोदी की सरकार में हर मंत्री के कामकाज पर पीएमओ की सीधी नजर रहती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो शायद ही 12 साल लगातर टिक पाते।

कांग्रेस का प्रोटेस्ट पार्ट-2

आज सभी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंच रहे संसद

नीट परीक्षा में धांधली और देश भर में हो रहे पेपर लीक के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस से सभी सांसद काले कपड़े पहनकार संसद भवन पहुंचेंगे और अपने विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस के इस बड़े विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और कड़ा संदेश देना है। पार्टी सांसदों ने एक साथ एकजुट होकर विरोध जताने की रणनीति बनाई है।

रविंद्र नाट्यग्रह पर फिर खर्च होंगे लाखों

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • शहर के पुराने रवींद्र नाट्य ग्रह को संवारने का काम फिर शुरू होने जा रहा है। यहां पर भीतरी भाग और बाहरी साज सजावट को लेकर नगर निगम ने लगभग 40-50 लाख रुपये का एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसकी मंजूरी पर अब काम की शुरुआत भी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि रवींद्र नाट्य नाट्य ग्रह में कई काम छोटे बड़े ऐसे होंगे जिनकी परेशानी लंबे समय से चल रही थी। यहां पर पार्किंग एरिया में एक और जहां कई सुधार काम होना है, बंद लाइटिंग, तरह तरह की लगाएगी खराब लगाई जाएगी एवं पर्याप्त रोशनी हो ऐसा काम यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर लंबे समय से कोई काम नहीं किया है, इसलिए भीतरी भाग में भी कई जगह सुधारने का काम होगा या न एक तरह से सौंदर्याकरण का काम किया जा रहा है। अलग अलग जगह नगर निगम कई ऐसे काम काम करेगा जिसमें लोगों के बैठने से लेकर बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी और बेहतर की जा रही है। यही कारण है कि नगर निगम द्वारा यहां पर बेहतर काम हो इसको लेकर जल्द ही टेंडर जारी होने जा रहे हैं। रविंद्र नाट्य ग्रह किसी समय काफी व्यस्त रहता था और धीरे-धीरे बदहाली के चलते इसे नगर निगम ने अपने हाथ में लिया है।

30 जून के प्रशासनिक तबादले बने प्रतिष्ठा का प्रश्न!

अभ्यावेदन की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी निरस्तीकरण की कवायद, सीईओ की लौटाई फाइल फिर आयुक्त को भेजी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • गत 30 जून को शिक्षा विभाग में हुए प्रशासनिक तबादले अब महज स्थानांतरण आदेश नहीं रह गए हैं, बल्कि कुछ तबादलों को लेकर मामला प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता नजर आ रहा है। 15 जुलाई को तबादलों के खिलाफ अभ्यावेदन की अंतिम समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी तबादले निरस्त कराने की कवायद जारी है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ तबादलों को निरस्त कराने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि तबादलों को निरस्त करने से संबंधित फाइल पहले इंदौर सीईओ के समक्ष पहुंची थी, लेकिन वहां से इसे वापस कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने इसी फाइल को अब ई-फाइल के माध्यम से लोक शिक्षण आयुक्त के पास भेज दिया है। माना जा रहा है कि फाइल के जरिए कुछ चुनिंदा तबादलों को निरस्त कराने के लिए उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वैसे इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री है और उनके अनुमोदन के बाद समय सीमा निकल जाने के बाद इस तरह के प्रयास किए जाने को शिक्षा विभाग में बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। बहरहाल जब शासन द्वारा जारी तबादला आदेशों के खिलाफ दावा-आपत्ति और अभ्यावेदन की प्रक्रिया के लिए 15 जुलाई अंतिम तारीख निर्धारित थी, तो समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कुछ तबादलों को निरस्त कराने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या अब प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी या फिर कुछ खास मामलों में दबाव और सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा?

सूत्रों की मानें तो कुछ तबादलों को लेकर मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि इन्हें निरस्त कराना अब प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया है। यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर फाइल लौटने के बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा और उसे अब लोक शिक्षण आयुक्त स्तर तक ले जाया गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या आयुक्त स्तर से कलेक्टर को कुछ तबादले निरस्त करने के निर्देश दिए जाते हैं या फिर 30 जून के आदेश अपनी मूल स्थिति में ही लागू रहेंगे।

सवाल जो उठ रहे हैं

- 15 जुलाई की अंतिम समय-सीमा के बाद भी तबादले निरस्त कराने की कोशिश क्यों?
- सीईओ द्वारा फाइल लौटाने के बाद उसे फिर उच्च स्तर पर क्यों भेजा गया?
- क्या कुछ चुनिंदा तबादलों को निरस्त कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है?

स्वच्छ शहर की सफाई के लिए नहीं मिल रहे कोई ठेकेदार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • शहर में रोड की सफाई के लिए नगर निगम को कोई एजेंसी 38 करोड़ रुपए की स्वीपिंग मशीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहली बार बुलाए टेंडर में एक भी एजेंसी नहीं आई। इसलिए दूसरी बार टेंडर जारी किए गए है। अगले महीने अगस्त में टेंडर आने के पहले 30 जुलाई को प्री बिड मीटिंग रखी गई है ताकि एजेंसियों से बात कर टेंडर डलवाए जा सकें।

शहर के मुख्य मार्गों से लेकर चौड़ी सड़कों, रिंग रोड और बायपास की सफाई के लिए निगम दिन-रात स्वीपिंग मशीनें चलाता है जो कि ठेके पर चलती है। अभी छोटी-बड़ी मिलाकर 25 मशीनें चल रही है। जिस एजेंसी के पास ठेका है, वह खत्म हो गया है।

इसके चलते स्वच्छ भारत मिशन के तहत रोड की सफाई के लिए 30 स्वीपिंग मशीन ठेके पर चलाने के लिए नए सिरे से टेंडर मार्च-2026 में जारी किए गए थे। सालाना 38 करोड़ रुपए खर्च कर ठेके पर यह स्वीपिंग मशीन चलाने का यह टेंडर था, जिसमें पहले 5 साल और फिर 2 साल के लिए ठेका देने के साथ मशीनों की ऑपरेटिंग के साथ मेंटेनेंस एजेंसी को ही करना था।

न्यूज़ ब्रीफ

स्टोआ पेरिस के ब्रांड एंबेसडर बने करण जौहर

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एनकम्पास डिजाइन इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रीमियम होम फैशन ब्रांड स्टोआ पेरिस के लिए फिल्म निर्माता और स्टाइल आइकन करण जौहर को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। करण जौहर फैशन और डिजाइन की गहरी समझ के लिए पहचाने जाते हैं। वह अब ब्रांड के आधुनिक, आकर्षक और अभिव्यक्तिपूर्ण होम लिविंग विजन को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत में उपभोक्ताओं की पसंद तेजी से बदल रही है। आज लोग अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि अपनी पहचान, व्यक्तित्व और लाइफस्टाइल का प्रतिबिंब मानने लगे हैं। इसी बदलते रुझान को ध्यान में रखते हुए स्टोआ पेरिस ऐसे होम डेकोर और होम फैशन उत्पाद पेश कर रहा है, जिनमें डिजाइन, शिल्पकला और व्यक्तिगत पसंद का संतुलित मेल देखने को मिलता है।

सेमसंग ने गैलेक्सी एआई डिवाइस पर 'बैक टू स्कूल' ऑफ़र लॉन्च किए

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● सेमसंग इंडिया ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम के लिए बैक टू स्कूल ऑफ़र की घोषणा की। इससे छात्र गैलेक्सी के एआई-पावर्ड लेटेस्ट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिन्हें पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान सीखने, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टार्ट स्कूल. स्टैंड आउट. गो फर्दर विद सेमसंग कैंपेन के तहत सेमसंग अपने सेमसंग प्रोग्राम के ज़रिए स्टूडेंट्स को खास फ़ायदे दे रहा है।

बढ़ती जीवनशैली संबंधी समस्याओं के बीच मस्तिष्क स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव, अनियमित खानपान, पर्याप्त नींद की कमी और उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। स्ट्रोक, डिमेंशिया, मिर्गी, पार्किंसन और माइग्रेन जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं में भी इनके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के अनुसार दुनिया में 3.4 अरब से अधिक लोग किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से प्रभावित हैं और ये बीमारियां वैश्विक स्तर पर विकलांगता का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके और समय पर जांच एवं उपचार के महत्व को समझाया जा सके।

नि:शुल्क दिव्यांग परीक्षण शिविर आयोजित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● समय पर इलाज मिलने से कई दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार यह इलाज नहीं करा पाते। ऐसे बच्चों को राहत देने के उद्देश्य से रविवार को अंकिताधाम सेवाधाम में नि:शुल्क दिव्यांग परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 150 बच्चों की जांच की गई। इनमें से 40 से 45 बच्चों का चयन नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए किया गया। इनका ऑपरेशन यूनिक हॉस्पिटल में नीमा ट्रस्ट के माध्यम से कराया जाएगा। शिविर के दौरान ऐसे बच्चों की भी जांच की गई, जो चलने-फिरने में असमर्थ थे। डॉक्टरों की टीम उनके बेड तक पहुंची और वहीं स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी। चयनित बच्चों का ऑपरेशन यूनिक हॉस्पिटल में नीमा ट्रस्ट के माध्यम से पूरी तरह नि:शुल्क किया जाएगा।

ओएमआर शीट में 305 नंबर, रिजल्ट में सिर्फ 64, हाई कोर्ट में लगाई याचिका

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नीट-यूजी 2026 के रिजल्ट में अंकों के अंतर का मामला अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ पहुंच गया है। झाबुआ के छात्र लोकेन्द्र सिंह खड़िया ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ याचिका दायर कर दावा किया है कि उसकी ओएमआर शीट और उत्तर कुंजी के आधार पर 305 अंक बनते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम में उसे सिर्फ 64 अंक दिए गए, जिससे उसका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रभावित हो रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने एनटीए से

ओएमआर शीट से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। याचिका के अनुसार छात्र ने 21 जून 2026 को आयोजित नीट-यूजी पुनर्परीक्षा दी थी। 14 जुलाई को एनटीए की वेबसाइट पर लॉगिन करने पर पहली बार उसकी ओएमआर शीट में भौतिकी और रसायन विज्ञान के उत्तर रिक्त दिखाई दिए। बाद में दोबारा लॉगिन करने पर दूसरी ओएमआर शीट मिली, जिसमें सभी उत्तर दर्ज थे। छात्र ने इसे ऑनलाइन सिस्टम की तकनीकी खामी बताया है। छात्र के अनुसार दूसरी ओएमआर शीट के आधार पर भौतिकी में 104, रसायन विज्ञान में 125 और जीव विज्ञान में 76 अंक बनते हैं। उसने एनटीए से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में ओएमआर शीट, मूल्यांकन प्रक्रिया और अंक गणना के स्वतंत्र सत्यापन की मांग की गई है। छात्र ने कहा है कि वह पुनर्मूल्यांकन नहीं, बल्कि रिकॉर्ड में हुई तकनीकी विसंगति को सुधारने की मांग कर रहा है।

जांच के बाद दोषियों पर होगी एफआईआर

नामांतरण घोटाले में गाज राजस्व उपायुक्त हटाए गए

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नगर निगम के चर्चित नामांतरण घोटाले में आखिरकार पहली बड़ी विभागीय कार्रवाई सामने आ गई है। घोटाले की जांच का दायरा अब निचले स्तर से आगे बढ़कर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने लगा है। इसी क्रम में निगम प्रशासन ने राजस्व उपायुक्त केशव सगर को राजस्व विभाग से हटाकर स्थापना एवं स्टोर शाखा में पदस्थ कर दिया है। वहीं, उनकी जगह उपायुक्त गरिमा पाटीदार को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम के इस फैसले को नामांतरण घोटाले में

अब तक की सबसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्रवाई माना जा रहा है। लंबे समय से घोटाले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह बदलाव इस बात का संकेत माना जा रहा है कि निगम प्रशासन जांच को गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। इस बीच नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने भी साफ कर दिया है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का ऋषि तीर्थ डकाचिया पर हुआ भव्य मंगल प्रवेश

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागरजी महाराज का आज डकाचिया स्थित ऋषि तीर्थ , एम एस जे फार्म हाउस पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आप अभी वहीं विराजमान है।

दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के प्रचार प्रमुख सतीश जैन ने बताया कि रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पूज्य मुनि श्री के पाद प्रक्षालन किये और आरती उतारी।सतीश जैन ने बताया कि ऋषि तीर्थ पहुंचने पर पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा , मध्यप्रदेश शासन सामाजिक संसद के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कार्याध्यक्ष सौरभ पाटोदी, महामंत्री देवेन्द्र सोगानी , कोषाध्यक्ष पिंकेश टोंग्या, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषभ पाटनी , संगठन महामंत्री जैनेश झांझरी सहित पदाधिकारियों , समाज श्रेष्ठियों ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया व चातुर्मास संबंधित चर्चा कर भव्य , आध्यात्मिक, धार्मिक,साधना ,तप, तपस्या ,धर्म चिंतन, स्वाध्याय, संयम , आत्मकल्याण, शक्ति , वैभव , भव्यता से पूर्ण मंगल प्रवेश पर चर्चा की ।

गैस पाइपलाइन विस्फोट में आखिरकार बीजेपी पार्षद सोनी पर हुई एफआईआर

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में 23 जून को वार्ड 31 में अवंतिका गैस लाइन के ऊपर ही बोरिंग करने से हुए ब्लास्ट में चार लोग झुलस गए थे। इस हादसे की नगर निगम द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट में बीजेपी पार्षद बालमुकुंद सोनी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे।

इंदौर में सत्ताधारी दल के नेता के प्रति ढीला रवैया अपना रही पुलिस को आखिरकार सख्ती दिखानी पड़ी। मामला वार्ड 31 में सुमन नगर में पार्षद बालमुकुंद सोनी द्वारा अवंतिका गैस पाइपलाइन पर ही बोरिंग करा देने का है, जिससे ब्लास्ट में चार लोग झुलस गए। इसे लेकर हाईकोर्ट इंदौर में मंगलवार, 21 जुलाई को एसीपी विजयनगर पराग सैनी पेश हुए। नगर निगम की जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर इसके लिए पार्षद बालमुकुंद सोनी (वार्ड 31) को

जिम्मेदार माना गया है। वहीं, इसके बाद भी पुलिस उन्हें बचा रही थी। कोर्ट ने दस दिन में जांच पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन विजयनगर पुलिस ने कहा कि पार्षद बयान देने नहीं आ रहे हैं। वहीं जब्त मशीन छोड़ने पर भी नाराजगी जताई। मंगलवार, 21 जुलाई को एसीपी पराग सैनी पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें पार्षद सोनी को भी आरोपी बना लिया गया है और जांच जारी है। इसके साथ ही कपिल शर्मा व अन्य भी आरोपी हैं। उधर यह बात भी आई कि घायल युवती का उपचार अहमदाबाद में हो रहा है और वहां 10 लाख रुपए का बिल बाकी है। मुफ्त उपचार होने के बाद भी शासन ने राशि नहीं दी है।

हाईकोर्ट में एसीपी ने यह बताया

इस हादसे के बाद अधिवक्ता रितेश इनानी ने जनहित याचिका दायर की है। इसके तहत घायलों को मुफ्त उपचार दिया जा रहा है और एक युवती को अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया गया है। हाईकोर्ट में जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने की बात भी उठी, इस पर पुलिस से जवाब मांगा गया।

'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर में प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव के संरक्षण, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. वी. पी. बैरागी के मार्गदर्शन में, कार्यक्रम के संयोजक प्रो. सुधीर कुमार छारी के निर्देशन में 21 जुलाई को 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की ओर से डी.एस.पी श्रीमती आशा सेजकर, निरीक्षक शहनाज बानो, उप निरीक्षक आशीष शर्मा सहित लगभग 20 पुलिस अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।

इंदौर की 9 डेयरियों पर मारे छापे, 37 सैंपल लैब भेजे, मोबाइल लैब से मौके पर भी जांच

खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन ने अब आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शहर की 9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ निरीक्षण कर 37 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए हैं। इनमें दूध, दही, पनीर, घी, मावा, पेड़ा, बर्फी, मिल्क केक और अन्य मिठाइयों के नमूने शामिल हैं। तीन प्रतिष्ठानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) के जरिए मौके पर ही प्रारंभिक जांच भी की गई, जबकि सभी नमूनों को अंतिम परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा

गया है। इस अभियान में 20 और 21 जुलाई को शहर के प्रमुख डेयरी प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान मदनी दूध डेयरी एंड स्वीट्स में पनीर और दही रखने वाले रेफ्रिजरेटर की साफ-सफाई रिसेंतोषजनक नहीं पाई मिली। हुए संचालक को तुरंत स्वच्छता व्यवस्था सुधारने, निर्धारित तापमान पर खाद्य पदार्थों का भंडारण करने और कोल्ड चेन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को शिवशक्ति मिल्क एंड स्वीट्स सेंटर, अंबे डेयरी एंड स्वीट्स और श्री कृष्ण दूध-दही भंडार में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मौके पर जांच की गई। खास बात यह रही किसे श्री कृष्ण दूध-दही भंडार में बिक रहे होकर इंदौर पहुंच रहे थे।

नेशनल आर्टिस्ट्स चैम्पियनशिप के दूसरे दिन ग्लैमर और हुनर का संगम

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● नेशनल आर्टिस्ट्स चैम्पियनशिप 2026 के दूसरे दिन मंगलवार को फीनिक्स सिटाडेल मॉल में हुनर, क्रिएटिविटी और ग्लैमर का अनूठा संगम देखने को मिला। देशभर से पहुंचे हेयर और ब्यूटी प्रोफेशनल्स ने अलग-अलग प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिनभर चली गतिविधियों के बीच हेयर आर्टिस्ट्री प्रतियोगिताएं और ग्रैंड फैशन शो खास आकर्षण रहे। अभिनेत्री कृति खरबंदा की मौजूदगी ने आयोजन में ग्लैमर का रंग भरा, वहीं चर्चित वेब सीरीज 'रक्तांचल' के निर्देशक रितम श्रीवास्तव, मुख्य अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेता निकितिन धीर भी आयोजन में शामिल हुए। दूसरे दिन हेयर आर्टिस्ट्री से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने हेयर कट, कलरिंग और क्रिएटिव स्टाइलिंग के जरिए अपनी कला और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों ने आधुनिक ट्रेंड्स के साथ अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्रस्तुत किया। लाइव प्रतियोगिताओं के दौरान इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने प्रतिभागियों के काम को परखा और उन्हें प्रोफेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आयोजन का ग्रैंड फैशन शो दूसरे दिन के प्रमुख आकर्षणों में रहा।

नगर परिषद में नवनियुक्त एल्डरमेनो का स्वागत किया

दैनिक इंदौर संकेत

सांवेर ● लंबे इंतज़ार के बाद मध्यप्रदेश शासन ने सोमवार को एल्डर मेन नियुक्ति की लिस्ट जारी की जिसमे केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट की सहमति से नगर परिषद अध्यक्ष संदीप चंगेडिया की अनुशंसा पर सांवेर विधानसभा की एक मात्र नगर परिषद सांवेर में विवेक महस्कर, पंकज जैन ,किरण जौहरी, ओमप्रकाश यादव को एल्डरमेन नियुक्त किया गया सभी की नियुक्ति पर नगर परिषद कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया जिसमे भाजपा जिला उपाध्यक्ष भरतसिंह चोहान,अध्यक्ष संदीप चंगेडिया ,वरिष्ठ नेता सुभाष जैन ,कुलवंत सिंह गांधी ,भगवती मकवाना ,पार्षद रायसिंह डाबी ,पप्पू भावसार ,घनश्याम शर्मा ,जयदीप क़ानूनगों ,इंद्रेश चावड़ा , मनोज शर्मा,राजेन्द्र वर्मा अमित लोधनिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी परागी गोयल एवं भाजपा नेताओं ने स्वागत कर बधाई प्रेषित की।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत किया वृक्षारोपण

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश के आदेशानुसार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति संबंधी औपचारिकताएँ संभागीय सेनानी (डिवीजनल कमांडेंट) की अध्यक्षता में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत किया वृक्षारोपण

न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में इंदौर झोन प्रदेश के प्रतिशत से आगे

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाडे की अध्यक्षता में संभागायुक्त कार्यालय में आज अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत राहत योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संभागायुक्त द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया कि इंदौर झोन का दोषसिद्धी 69 प्रतिशत है, जो प्रदेश के कुल प्रतिशत से अधिक है।

इस संबंध में खंडवा जिले में किये गये दोषसिद्धी की सराहना की गई। बैठक में इंदौर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त और अभियोजन अधिकारी शामिल हुए। संभागायुक्त कार्यालय इंदौर से आईजी अनुराग, संयुक्त आयुक्त (विकास) श्रीमती शिवानी वर्मा, डीसीपी राजेश त्रिपाठी, जनजातीय कार्य विभाग के उपायुक्त गणेश भाभर, अजाक्स के पुलिस अधीक्षक शेरसिंह भूरिया, अभियोजन अधिकारी भदौरिया एवं संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

47 वीं वर्षगांठ पर चोइथराम से परामर्श पर मरीज़ों को तीन गुना स्वास्थ्य लाभ

900 रुपए पर 2700 रुपए की सेवाएँ लेने का लाभप्रद अवसर

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● चोइथराम हॉस्पिटल द्वारा अपनी 47 वें स्थापना दिवस पर मरीजों के लिए विशेष सेवाएँ प्रस्तुत की जा रही है। हॉस्पिटल और क्लिनिक पर डॉक्टर परामर्श हेतु आने वाले मरीजों को 900 रुपए अदा करने पर 3 गुना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अर्थात् उन्हें 900 रुपए पर 2700 रुपए की सेवाएँ मिलेगी। वे इसके तहत डॉक्टर परामर्श के साथ 900 रुपए के 2 वाउचर प्राप्त करेंगे। इसमें से एक वाउचर का इस्तेमाल पैथोलॉजी टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, स्ल्ड्ढ़, क्क्षञ्ज स्कैन, फिज़ियोथेरेपी या अन्य किसी विशेषज्ञ के परामर्श में बिना किसी शर्त के कर सकते हैं। दूसरे वाउचर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में होने वाले एडमिशन के दौरान कर सकते हैं।

इस बारे में बताते हुए हॉस्पिटल के सीएफओ श्री रोहित झंवर ने बताया कि 'पैशेंट्स को उनके अदा की गई राशि का अधिक लाभ हो यही सच्ची चैरिटी है। मॉडर्न हॉस्पिटल सोल्यूशंस में डॉक्टर परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सुपर स्पेशलिटी। इस सुविधा से मरीज़ को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क क्रॉस कंसल्टेशन मिल सकेगा। जिस से निदान आसान हो जाता है।

डीएवीवी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट

छात्रों और अभिभावकों को किया अलर्ट, साइबर सेल में शिकायत दर्ज

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी के मामले से जूझ रहा है, जहां विश्वविद्यालय के नाम और आधिकारिक लोगो का अनधिकृत रूप से उपयोग कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेषकर इंस्टाग्राम पर कई पेज बनाए गए हैं। इन अनाधिकृत पेजों के माध्यम से गलत जानकारी प्रसारित होने और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचने की आशंका के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इंदौर साइबर क्राइम में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

फर्जी इंस्टाग्राम पेजों की जानकारी मिलते ही साइबर क्राइम में दर्ज कराई शिकायत

कुलसचिव प्रज्वल खरे के अनुसार, इंस्टाग्राम पर बनाए गए इन अनधिकृत पेजों की जानकारी विश्वविद्यालय प्रबंधन को हाल ही में मिली। सूचना मिलते ही, मामले की गंभीरता को समझते हुए, कुलसचिव द्वारा बिना किसी विलंब के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत का मुख्य उद्देश्य इन अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना और विश्वविद्यालय की डिजिटल पहचान को सुरक्षित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे पेजों द्वारा डाली गई कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक जानकारी नहीं मानी जा सकती और वह लोगों को गलत दिशा में ले जा सकती है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रज्वल खरे ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डीएवीवी के नाम और उसके लोगो का अधिकारिक रूप से उपयोग करने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय को है। इसके बावजूद, कुछ अज्ञात व्यक्तियों या समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे पेज बनाए गए हैं, जो विश्वविद्यालय की पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पेज न केवल डीएवीवी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक लोगो को भी लगाकर आम जनता और छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रज्वल खरे ने आगे बताया कि अनधिकृत रूप से नाम और लोगो का उपयोग करते हुए कुछ लोगों ने ये पेज बनाए हैं। इन पेजों पर डाली गई जानकारियां, आम लोगों को यह विश्वास दिला सकती हैं कि वे विश्वविद्यालय के आधिकारिक पेज से प्राप्त हुई हैं।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, बुधवार 22 जुलाई 2026

न्यूज ब्रीफ

संस्कृति के संवर्धन के बिना कोई देश, समाज या परिवार समृद्ध नहीं हो सकता - स्वामी प्रणवानंद

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पेट की तरह आत्मा को भी भूख लगती है। भोजन से तो पेट की भूख मिट जाती है लेकिन आत्मा की भूख भजन, सत्संग और कथा श्रवण से ही मिटेगी। भारत संस्कारों की भूमि है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों और मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। विवाह भी एक संस्कार है। पश्चिमी संस्कृति में विवाह अनुबंध या सौदा होता है, लेकिन भारत में यह सात जन्मों का रिश्ता माना जाता है। संस्कृति के संवर्धन के बिना कोई देश, समाज या परिवार समृद्ध नहीं हो सकता। विवाह जैसे संस्कार के कारण ही भारतीय समाज आज भी मर्यादित, संस्कारवान और आदर्शों से बंधा हुआ है। ये प्रेरक विचार हैं वृन्दावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती के, जो उन्होंने गीता भवन में भक्त मंडल एवं अखंड प्रणव योग वेदांत पारमार्थिक न्यास के तत्वावधान में चल रहे भागवत ज्ञान यज्ञ में रुक्मणी विवाह एवं सुदामा चरित्र प्रसंग की व्याख्या के दौरान व्यक्त किए। कथा में रुक्मणी विवाह का उत्सव पूरे जोश एवं उत्साह से मनाया गया।

भोपाल में भी हुई बाणेश्वरी कावड़ यात्रा की गूंज

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मालवांचल की सबसे बड़ी 'बाणेश्वरी कावड़ यात्रा' की गूंज मंगलवार को राजधानी भोपाल में भी होती रही। यात्रा संयोजक विधायक गोलू शुक्ला ने विधायक रमेश मेंदोला के साथ राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट कर उन्हें इस यात्रा का न्योता भी दिया और संस्था बाणेश्वरी की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। मुख्यमंत्री सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने कावड़ यात्रा को भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के लिए गौरवशाली प्रसंग बताते हुए विधायक गोलू शुक्ला को आश्वस्त किया कि वे यात्रा के दौरान अपनी सुविधानुसार कहीं भी शामिल होकर इसका पुण्य लाभ अवश्य उठाएंगे। नेताओं से सौजन्य भेंट के दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा एवं अन्य सहयोगी साथी भी उपस्थित थे। विधायक गोलू शुक्ला ने उन्हें बताया कि बाणेश्वरी कावड़ यात्रा इस बार रविवार 2 अगस्त को इंदौर से दोपहर 1 बजे बस द्वारा महेश्वर और वहां से सोमवार, 3 अगस्त को सुबह 7 बजे मां नर्मदा के दुग्धाभिषेक एवं चुनरी समर्पण के बाद महाकालेश्वर उज्जैन के लिए प्रस्थित होगी। कावड़ यात्रा का समापन उज्जैन में सोमवार 10 अगस्त को सुबह 4 बजे भगवान महाकालेश्वर के जलाभिषेक के साथ होगा।

इंदौर बना तीर्थ : 2026 चातुर्मास में विराजेंगे राष्ट्रसंत सुधासागर महाराज

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● सर सेठ हुकुमचंद जी एवं लोकमाता देवी अहिल्याबाई की धर्म नगरी इंदौर के लिए ऐतिहासिक एवं परम सौभाग्य का क्षण आया है। परम वंदनीय, राष्ट्र संत, तीर्थचक्रवर्ती, निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज ससंघ* का वर्ष 2026 का पावन वर्षायोग चातुर्मास तीर्थ स्वरूप आदिनाथ जिनालय, छत्रपति नगर स्थित दालाल बाग, इंदौर (म.प्र.) में होना सुनिश्चित हुआ है।यह जानकारी धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने देते हुए इस घोषणा को इंदौर नगरी के लिए अत्यंत गौरव, श्रद्धा एवं आध्यात्मिक सौभाग्य का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास से इंदौर की धरा धन्य होगी। यहाँ की हवाओं में धर्म की सुगंध बहेगी और श्रद्धालुओं को आत्मकल्याण का अनुपम मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

बैठक में तय की 355 निजी कॉलेजों की फीस, मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में हुआ खुलासा

भोपाल (एजेंसी) ● निजी शिक्षण संस्थानों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए हैं। विधानसभा में सरकार के जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति ने चार वर्षों में 5062 निजी शिक्षण संस्थानों की फीस तय की, जबकि एक बैठक में ही 355 संस्थानों का शुल्क निर्धारण कर दिया गया। उपाध्याय ने सवाल उठाया कि इतने कम समय में आय-व्यय और अन्य दस्तावेजों का गहन परीक्षण कैसे संभव है। विधायक पंकज उपाध्याय के प्रश्न के लिखित उत्तर में तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति ने वर्ष 2022 से 2025-26 तक 5062 निजी शिक्षण संस्थानों का शुल्क निर्धारण किया है।

सरकार ने यह भी बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिकतम 15 दिन में आवेदन का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट समिति को देता है, जिसके आधार पर फीस निर्धारण किया जाता है। सरकार के इस जवाब के बाद पंकज उपाध्याय ने शुल्क निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पर सवाल

खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनके मूल प्रश्न का यह हिस्सा अनुत्तरित रहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कितने दिनों में कितने आवेदनों का परीक्षण किया। उनका कहना है कि राजपत्र, 2008 के प्रावधानों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी भी शिक्षण संस्थान के आय-व्यय, तुलनापत्र और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का गहन परीक्षण करना होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्थान से स्पष्टीकरण भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदनों का परीक्षण व्यावहारिक नहीं लगता।

उपाध्याय ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025-26 के दौरान एक ही बैठक में 355 निजी शिक्षण संस्थानों की फीस तय कर दी गई। उन्होंने कहा कि समिति को निरीक्षण दल की रिपोर्ट, विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट और संस्थानों के आय-व्यय का परीक्षण करने के बाद ही निर्णय लेना होता है। ऐसे में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों का शुल्क निर्धारण गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने नर्सिंग कॉलेजों का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि हर वर्ष 60 से 100 नर्सिंग संस्थानों की फीस निर्धारित की जाती है, जबकि इनमें से कई संस्थानों के नियमों के विपरीत संचालित होने के आरोप पहले से सामने आते रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसे संस्थानों के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट और निरीक्षण दल ने क्या परीक्षण किया तथा किन मानकों के आधार पर उनका शुल्क निर्धारित किया गया। पंकज उपाध्याय ने निजी शिक्षण संस्थानों की फीस निर्धारण प्रक्रिया की सीबीआई या किसी उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर मुनाफाखोरी पर रोक लगाई जानी चाहिए और समान पाठ्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश में एक समान शुल्क व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने यूसीसी लागू कर इतिहास रचा-सुमित मिश्रा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने मध्यप्रदेश विधानसभा सदन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने यूसीसी लागू कर इतिहास रचा दिया है। भाजपा सरकार का यह निर्णय मध्यप्रदेश के इतिहास में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक अध्याय है। यूसीसी महिलाओं और बेटियों को समाज में सुरक्षा और बराबरी का अधिकार दिलाएगा। इस कानून से सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण के साथ संवैधानिक मूल्यों को नई मजबूती मिलेगी।

मिश्रा ने कहा कि विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित कर मध्यप्रदेश ने समान न्याय,समान अधिकारों की भावना को साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के समान न्याय और समान अधिकारों की भावना को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक समरसता तथा पारदर्शी कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह एक दूरगामी और प्रभावी निर्णय सिद्ध होगा। समान नागरिक संहिता विधेयक का विधानसभा से पारित होना संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में निहित उस भावना को साकार करने वाला कदम है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की परिकल्पना की गई है। समान नागरिक संहिता समाज के सभी वर्गों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी,जिससे नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी पंथ अथवा व्यक्तिगत परंपराओं के आधार पर अलग-अलग न होकर संविधान की भावना के अनुरूप समान रूप से लागू होंगे।यह निर्णय न्यायिक समानता, सामाजिक समरसता और सुशासन को नई मजबूती प्रदान करेगा।

अपनी मेहनत और समर्पण से बड़वानी बन रहा देश में कृषि, उद्यमिता एवं नवाचार का उदाहरण : मुख्यमंत्री

बड़वानी की लाल मिर्च को दिलाएंगे जीआई टैग

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बड़वानी के नाम में ही प्रकृति विराजी है। क्योंकि इस जिले का नामकरण ही 'बड़ के वन' यानी बरगद के विशाल वृक्षों से हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे बरगद का वृक्ष विशाल छाया, निरंतर मिलने वाली हरियाली का प्रतीक है, वैसे ही बड़वानी जिला यहां के लोगों की मेहनत और नवाचारों के बल पर पूरे देश में कृषि, उद्यमिता, नवाचार का नवीन उदाहरण बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मप्र विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष से बड़वानी जिले में हुए बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि बलराम कृषि महोत्सव सबके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने किसानों विशेषकर युवा किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे बढ़-चढ़ कर इस कृषि महोत्सव में सहभागिता करें।

बड़वानी जिले में मनाया गया बलराम कृषि महोत्सव

खेती में तकनीक और नवाचार को शामिल करें। एग्री-स्टार्टअप प्रारंभ करें, आधुनिक कृषि तकनीक सीखें। सरकार की योजनाओं का लाभ और कृषि विशेषज्ञों की समुचित सलाह लें, सरकार आपके हर कदम पर साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सहभागिता से ही बलराम कृषि महोत्सव सफल होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे मिर्च उत्पादक किसान अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक खेती, आधुनिक ग्रेडिंग और उन्नत पैकेजिंग को अपना रहे हैं। इससे बड़वानी की मिर्च की मांग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बड़वानी की लाल मिर्च को 'जीआई टैग' दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। एक बार यह टैग मिल गया, तो दुनिया के बाजारों में बड़वानी की मिर्च का पेटेंट हो जाएगा और ग्लोबल ब्रांड के रूप में नई पहचान मिलेगी।

कई कंपनियों नकली ब्रांडेड उत्पादों खेप जब्त, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

भोपाल (एजेंसी) ● शहर में नकली ब्रांडेड उत्पादों के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच ने करीब 10 लाख रुपए कीमत का नकली दैनिक उपयोग का सामान जब्त किया है। कार्रवाई में सोहेल उर्फ रिहान (34) निवासी करोंद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से ब्रांडेड कंपनियों के नाम से तैयार किए गए सर्फ, शैंपू, फेस क्रीम, विक्स वेपोरब, ईनो, हेयर ऑयल, एवरेस्ट मसाले समेत बड़ी मात्रा में नकली उत्पाद बरामद हुए हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अहमदाबाद (गुजरात) से कम कीमत पर नकली सामान खरीदकर भोपाल लाता था और उसे असली ब्रांड के नाम पर शहर की किराना दुकानों तक पहुंचाता था। पुलिस अब इस पूरे सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कबाड़खाना इलाके में एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के जरिए नकली ब्रांडेड सामान भेजने की तैयारी में है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने मीनार कांटा के सामने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। मौके से कार्टन और बोरियों में भरा नकली सामान बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नकली उत्पाद अहमदाबाद से खरीदकर भोपाल में विभिन्न दुकानों पर सप्लाई करता था। उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और 65 सहित अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

जांच में पता चला कि नकली उत्पादों की पैकिंग और रैपर इस तरह तैयार किए गए थे कि आम ग्राहक के लिए उन्हें असली और नकली में पहचानना लगभग मुश्किल था। कम कीमत का लालच देकर ये उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत के साथ-साथ उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा था।

वहीं कमल ट्रेडर्स (फूटा मकबरा) और जैन गृह उद्योग (गांधीनगर) में आरोपी द्वारा सामान पहले ही बेचने की बात सामने आई है।

इंदौर में सुबह से रिमझिम, अब तेज बारिश का इंतजार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ●इंदौर में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश की प्रतीक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। सप्ताह की शुरुआत से ही आसमान में बादलों का डेरा जमा हुआ है, लेकिन झमाझम पानी गिरने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। अगले दिन सुबह से ही शहर के कुछ अलग हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, परंतु इंदौरवासियों को अब भी एक अच्छी और तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। इंदौर में दिनभर रिमझिम बारिश हुई।

पीपल्याहाना क्षेत्र के अग्रवाल संगठनों ने बरसाना गार्डन पर जबरदस्त स्वागत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के 26 जुलाई को हो रहे द्विवार्षिक चुनाव के लिए मैदान में उतरी 'जय अग्रसेन खाटू श्यामजी पैनल' को शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में बम्पर समर्थन मिल रहा है। अब तक मालवा मील, परदेशीपुरा, विजय नगर, अन्नपूर्णा, नवलखा, आनंद नगर के बाद अब पीपल्याहाना क्षेत्र में भी पैनल के सभी उम्मीदवारों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पैनल द्वारा समाज हित में हॉस्पिटल, कॉलेज और छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के लिए कोचिंग क्लासेज सहित समाज के सभी वर्गों के लिए समय-समय पर धार्मिक एवं शैक्षणिक यात्राओं के संकल्प का चारों ओर स्वागत किया जा रहा है। सोमवार को पीपल्याहाना क्षेत्र के अग्रवाल संगठनों ने बरसाना गार्डन पर पैनल के सभी उम्मीदवारों को आमंत्रित कर उन्हें महाराजा अग्रसेन एवं कुलदेवी महालक्ष्मी की साक्षी में प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प व्यक्त किया। बरसाना गार्डन पर आयोजित इस मिलन समारोह में अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष अरविन्द बागड़ी, समाजसेवी नारायण अग्रवाल 420 पापड़, वासु टिबडेवाल, श्रीमती प्रतिभा मित्तल, पुष्पा गुप्ता, महेश अग्रवाल, दिनेश गोयल प्रिंस, अर्पित विनोद बंसल, अमित ब्रजमोहन अग्रवाल, आलोक बंसल, कृष्णा गुप्ता, रविप्रकाश बंसल, अनिमेष अग्रवाल, मेघा आनंद अग्रवाल, लता मनीष गर्ग एवं पिंकी पीयूष बंसल सहित करीब 450 समाज बंधुओं ने पैनल के सभी उम्मीदवारों को पुष्प मालाओं से लादकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प किया।

13 दिन बाद बारिश से खरीफ फसलों को मिला जीवनदान, सोयाबीन, कपास, मक्का और मिर्च फसलों को राहत मिली

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ●मंगलवार को 13 दिन के अंतराल के बाद रिमझिम बारिश हुई। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर 2 बजे तक जारी रही। जिले के भगवानपुरा और झिरनिया क्षेत्रों में भी तेज बारिश दर्ज की गई। इस बारिश के कारण 24 घंटे के भीतर तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 28.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

इस बारिश से सोयाबीन, मिर्च, मक्का और कपास जैसी खरीफ फसलों को जीवनदान मिला है। किसान राजेश पटेल ने बताया कि यह बारिश कपास, मिर्च और मक्का की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिससे उनकी तेजी से बढ़वार होगी।

जिला भू-अभिलेख कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक औसत 10.2 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल इसी अवधि तक 8.6 इंच बारिश हुई थी। जिले की कुल औसत बारिश 32.6 इंच है। खरीफ सीजन 2026-27 में जिले में लगभग 4 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलें लगाई गई हैं।

सांध्य दैनिक इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357,94245-83000

सम्पादकीय

संसद में संवाद से ही निकलेगा गतिरोध, टकराव से नहीं चलेगा लोकतंत्र

विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वे जनता की नुमाइंदगी करते हुए उनकी आवाज, उनके मुद्दों को संसद में उठाएं और सरकार से जवाब मांगें। यह एक आदर्श स्थिति है कि देश की संसद में विधायी कामकाज सामान्य तरीके से पूरा हो। इसे सुनिश्चित करने की जितनी जिम्मेदारी विपक्षी दलों की है, उससे ज्यादा बड़ा दायित्व खुद सरकार का है कि वह विवादित मुद्दों पर संवाद के जरिए आमराय बनाकर सदन का काम सुचारु रूप से पूरा होने की स्थितियां निर्मित करे। इसमें वैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जो देश में किन्हीं वजहों से अचानक खड़े हो जाते हैं और जनता की ओर से उन पर सरकार से जवाब की उम्मीद या मांग की जाती है। विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वे जनता की नुमाइंदगी करते हुए उनकी आवाज, उनके मुद्दों को संसद में उठाएं और सरकार से जवाब मांगें। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि सरकार को इस तरह की स्थितियों में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपनी ओर से पहल करना कोई गैर-महत्त्व की बात लगती है। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ता है। सवाल है कि देश की संसद अगर जनता के मुद्दों पर विचार और बहस के जरिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं, तो आखिर किसलिए है! गौरतलब है कि मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इसलिए स्थगित कर दी गई कि विपक्षी दल सरकार से इस पर जवाब चाहते थे कि एक दिन पहले दिल्ली में संसद मार्च के आह्वान के तहत जुटे युवाओं पर जिस तरह की पुलिस कार्रवाई देखी गई, उसकी जिम्मेदारी तय हो। मगर इसके बजाय दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्वाभाविक ही विपक्षी दलों को यह आरोप लगाने का मौका मिला कि हम पुलिस के अत्याचार, प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने और उनके घायल होने के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने तथा गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने चर्चा का अवसर नहीं दिया, हमारा मुंह बंद करा दिया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की ओर से अगर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विडंबना यह है कि न तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करके कोई हल निकालने की कोशिश की गई और न ही संसद में इस मसले पर बहस के लिए सकारात्मक माहौल निर्मित किया जा रहा है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ क्यों लामबंद हुए किसान

किसानों द्वारा दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत का ऐलान किया गया है । इससे पहले दिल्ली, जालंधर और जम्मू नेशनल हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. शंभू बॉडर पर किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका गया है । यहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य कई राज्यों से जुड़े किसान और सामाजिक संगठनों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है । किसान नेताओं ने अलग-अलग जगहों से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोके जाने का विरोध किया है व विवाद बढ़ता ही जा रहा है । गौरतलब है कि इस पूरे विवाद की जड़ में दोनों देशों की कृषि संरचना का बुनियादी और जमीन-आसमान का अंतर है। अमेरिका में कृषि कोई जीवन जीने का तरीका नहीं, बल्कि एक विशाल कॉरपोरेट उद्योग है। वहाँ औसतन एक किसान के पास सैकड़ों या हजारों एकड़ जमीन होती है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीक, जीएम फसलों और भारी-भरकम मशीनों से खेती की जाती है। इसके विपरीत, भारत की हकीकत बिल्कुल जुदा है। भारत में लगभग 80 से 85 प्रतिशत किसान 'छोटे और सीमांत' वर्ग में आते हैं, जिनके पास दो से ढाई एकड़ या उससे भी कम जमीन है। भारतीय किसान के लिए खेती केवल व्यापार नहीं, बल्कि उसके परिवार के पेट भरने और जिंदा रहने का एकमात्र जरिया है। जब भारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों के दरवाजे पूरी तरह खोले जाएंगे, तो यह मुकाबला दो बराबरी के खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि एक महाबली और एक बेहद कमजोर इंसान के बीच होगा। भारतीय सीमांत किसान किसी भी कीमत पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कृषि कंपनियों के उत्पादन पैमाने और उनकी आक्रामक मूल्य निर्धारण नीति का सामना नहीं कर पाएगा। नतीजा यह होगा कि घरेलू बाजार में भारतीय किसानों की फसलों को कोई खरीदार नहीं मिलेगा।

अमेरिकी सरकार अपने देश के कॉरपोरेट फार्मिंग सेक्टर को हर साल अरबों डॉलर की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब्सिडी देती है। विश्व व्यापार संगठन के मंचों पर अमेरिका अक्सर विकासशील देशों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी जीवन रक्षक प्रणालियों पर सवाल उठाता है, लेकिन खुद अपने अमीर किसानों को 'ग्रीन बॉक्स' और अन्य श्रेणियों के तहत भारी वित्तीय मदद देता है। इस भारी सब्सिडी के कारण अमेरिकी कृषि उत्पादों (जैसे मक्का, सोयाबीन, कपास और पोल्ट्री उत्पाद) की उत्पादन लागत बेहद कम हो जाती है। यदि बिना किसी ठोस टैरिफ के इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में डंप करने की अनुमति मिल जाती है, तो भारतीय मंडियों में हाहाकार मच जाएगा। भारत का किसान जो फसल भारी लागत,

महंगे डीजल, महंगे बीज और खाद के जरिए पैदा करता है, अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पाद उससे आधी कीमत पर उपलब्ध होने लगेंगे। यह भारतीय खेती की रीढ़ तोड़ने जैसा होगा। यह मुक्त व्यापार नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुचित प्रतिस्पर्धा है जो भारतीय किसानों को उनकी ही जमीन पर पराया और दिवालिया बना देगी।

इस ट्रेड डील का सबसे संवेदनशील और खतरनाक पहलू भारत का डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और खास बात यह है कि यह श्वेत क्रांति किसी बड़े कॉरपोरेट घराने ने नहीं, बल्कि देश की करोड़ों ग्रामीण महिलाओं और छोटे पशुपालकों ने अपने एक या दो मवेशियों के दम पर खड़ी की है। डेयरी उद्योग भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए संकट के समय एटीएम की तरह काम करता है, जो उन्हें सूखा या फसल बर्बादी के वक्त भी नकदी की गारंटी देता है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने डेयरी बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले। अमेरिकी डेयरी उद्योग पूरी तरह मशीनीकृत और औद्योगिक स्तर पर संचालित होता है। इसके अलावा, वहाँ पशुओं को दिए जाने वाले चारे और हार्मोन को लेकर जो नियम हैं, वे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के विपरीत हैं। अमेरिका में गायों को 'ब्लड मील' (रक्त और मांस से बना चारा) दिया जाता है, जिसे भारतीय समाज और यहाँ के किसान स्वीकार नहीं कर सकते। यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद, जैसे कि सस्ता मिल्क पाउडर, चीज और मट्ठा भारतीय बाजार में आ गए, तो देश के सहकारी डेयरी ढांचे (जैसे अमूल और अन्य राज्य स्तरीय कॉपरेटिव्स) को अपूरणीय क्षति होगी। करोड़ों महिलाओं के हाथ से उनका रोजगार छिन जाएगा, जो अंततः ग्रामीण भारत में गरीबी और कुपोषण को और बढ़ाएगा। इसी तरह, अमेरिकी 'चिकन लेग्स' (मुर्गे के पैर) की डंपिंग से भारत का पोल्ट्री उद्योग, जिसमें लाखों छोटे उद्यमी शामिल हैं, पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच जाएगा।

किसान संगठनों की नाराजगी का एक और बड़ा और जायज कारण इस पूरी वार्ता प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव होना है। ट्रेड डील से जुड़े फैसले बंद कमरों में, बिना किसी सार्वजनिक बहस या हितधारकों से चर्चा किए लिए जा रहे हैं। भारत के संविधान में कृषि को 'राज्य सूची' का विषय माना गया है, जिसका सीधा मतलब है कि कृषि से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में राज्य सरकारों की सहमति और भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। परंतु केंद्र सरकार ने इस समझौते के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते समय न तो किसान यूनियनों को विश्वास में लिया और न ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों या कृषि मंत्रियों से कोई सार्थक संवाद किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह रवैया अत्यंत चिंताजनक है। जब देश की आधी आबादी के जीवन को प्रभावित करने वाली नीति गुपचुप तरीके से तैयार की जाती है, तो जनता का व्यवस्था से भरोसा उठना लाजमी है। किसानों की यह मांग पूरी तरह तार्किक है कि सरकार इस समझौते से जुड़े सभी मसौदे और दस्तावेजों को सार्वजनिक करे और संसद में इस पर विस्तृत बहस कराई जाए।

कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यह किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा की पहली कतार है। 1960 के दशक में भारत ने 'पीएल-480' (PL-480) के तहत अमेरिकी गेहूं पर निर्भरता का जो दंश झेला था, उसे देश भूला नहीं है। उस समय अमेरिका ने खाद्यान्न आपूर्ति को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसके बाद ही भारत ने 'हरित क्रांति' के जरिए खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की। आज यह ट्रेड डील हमें वापस उसी खतरनाक रास्ते पर ले जाने का जोखिम पैदा कर रही है। यदि भारत अपनी खाद्य जरूरतों के लिए अमेरिकी आयात पर निर्भर हो जाता है, तो देश की 'खाद्य संप्रभुता' खतरे में पड़ जाएगी। कल को यदि कोई भू-राजनीतिक तनाव होता है, तो अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स हमारे देश की खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भारत कभी भी अपनी 140 करोड़ जनता की थाली की चाबी किसी विदेशी ताकत या विदेशी कंपनियों के हाथ में नहीं सौंप सकता।

अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौतों में हमेशा 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' और पेटेंट कानूनों को कड़ा करने की शर्त शामिल होती है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि मोंसैटो और कारगिल चाहती हैं कि भारत के बीज कानूनों में बदलाव किया जाए ताकि वे बीजों और कृषि प्रौद्योगिकियों पर अपना पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर सकें। भारत में पारंपरिक रूप से किसान अपनी फसल से ही अगले साल के लिए बीज बचाकर रखते हैं या आपस में विनिमय करते हैं। अमेरिकी दबाव में यदि 'प्रोटेक्टेड वैरायटी' और सख्त पेटेंट कानून लागू किए गए, तो किसानों का अपने ही बीजों पर अधिकार खत्म हो जाएगा। उन्हें हर सीजन में महंगे पेटेंटेड बीज कॉर्पोरेट कंपनियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे न केवल खेती की लागत कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि भारत की समृद्ध जैव-विविधता और पारंपरिक कृषि ज्ञान भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का यह देशव्यापी आंदोलन केवल फसलों के दाम की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह इस देश के ग्रामीण समाज के वजूद की लड़ाई है। यह नीतिगत दिशा तय करने का एक निर्णायक मोड़ है कि भारत का विकास मॉडल कैसा होना चाहिए। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ चंद कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए करोड़ों किसानों और खेतिहर मजदूरों को उनके खेतों से बेदखल कर दिया जाए? या हम एक ऐसा समावेशी भारत चाहते हैं जहाँ आर्थिक नीतियों के केंद्र में देश का गरीब, किसान और आम नागरिक हो?

सरकार को यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति की चमक देश के अन्नदाताओं के आंसुओं पर नहीं बिखेरी जा सकती। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संतुष्ट करने के लिए भारतीय कृषि की बलि चढ़ाई गई, तो इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम बेहद भयावह होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन होगा, बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाएगी और देश में सामाजिक असंतोष की एक नई लहर पैदा होगी। समय की मांग है कि सरकार तुरंत इस आत्मघाती ट्रेड डील पर आगे बढ़ने से रुके, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता की मेज पर बुलाए और देश की खाद्य सुरक्षा व किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक नई न्यायसंगत नीति तैयार करे। देश का विकास किसानों की तबाही की कीमत पर कभी नहीं हो सकता वो भी उस समय जब पंजाब का चुनाव सर पर हो तो पंजाब के किसानों से पंगा लेना उचित नहीं होगा ।

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार,
लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

आंचलिक

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने ली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट ईंधन वितरित की सतत् मॉनिटरिंग करें - कलेक्टर

अजय नलवाया (7879800048)

धार ● दैनिक इंदौर संकेत

जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से आज कलेक्टर सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा और प्रशासनिक अमले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने जिले में पिछले कुछ समय में हुए रोड एक्सीडेंट्स की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि हर उस कारण का गहराई से पता लगाया जाए जिससे दुर्घटना हुई है। उन्होंने घायलों और मृत व्यक्तियों से जुड़े मामलों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) को चिह्नित कर वहाँ तुरंत गति अवरोधक, संकेतक (साइन बोर्ड) और लाइटिंग जैसे सुधारात्मक उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में हादसों को रोका जा सके। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर ने

जिला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से मैदान में उतरने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन वितरित न किया जाए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को इसकी सतत् मॉनिटरिंग करे। इसके साथ ही बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हेतु विभिन्न माध्यमों से जनजागरुकता लाए।

भोजशाला पर राष्ट्रीय व्याख्यानमाला सांस्कृतिक पुनर्जागरण रहेगा केंद्रीय विषय

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● भोजशाला को लेकर एक राष्ट्रीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी गुरुवार को धार के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। राजा भोज स्मृति व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश कर्मा ने बताया कि यह विशेष राष्ट्रीय व्याख्यानमाला 24 जुलाई (शुक्रवार) को शाम 4 बजे जेएमडी स्थित मिलन महल में होगी। इसका विषय 'भोजशाला भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण - दिशा, दृष्टि एवं दायित्व' रखा गया है। डॉ. कर्मा ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल भोजशाला तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, ज्ञान परंपरा, ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक आत्मगौरव और राष्ट्रीय दायित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का मंच बनेगा। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित विद्वान इतिहास, वैचारिक दृष्टि और भविष्य की दिशा पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। व्याख्यानमाला में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव और प्रख्यात इतिहासकार डॉ. बालमुकुंद पाण्डेय भोजशाला के ऐतिहासिक पक्ष, उपलब्ध साक्ष्यों और भारतीय इतिहास में उसके महत्व पर व्याख्यान देंगे। प्रख्यात चिंतक एवं लेखक प्रशांत पोल भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विमर्श और भारतीय सभ्यता की निरंतरता के वैचारिक पक्ष पर अपने विचार रखेंगे।

मंदिर क्षेत्र से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, ओंकारेश्वर में पॉलीथिन पर नगर परिषद की कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में नगर परिषद ने मंगलवार को प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलीथिन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से गौमुख घाट तक की गई कार्रवाई में करीब 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई। नगर परिषद ने दुकानदारों को दोबारा पॉलीथिन का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोनिका पारधी के मार्गदर्शन में स्वच्छता टीम ने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से गौमुख घाट तक सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों से करीब 10 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलीथिन जब्त की गई।

नगर परिषद की टीम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालानी कार्रवाई के साथ नियमानुसार सख्त

कदम उठाए जाएंगे।

स्वच्छता प्रभारी जितेंद्र हटवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नगर में पॉलीथिन प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, नालियां जाम होती हैं और मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

नगर परिषद ने व्यापारियों और नागरिकों से कपड़े, कागज तथा अन्य पर्यावरण अनुकूल थैलों का उपयोग करने की अपील की है। परिषद ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

26 जुलाई को धार में 'Say No To Drugs' मैराथन, नशामुक्ति का संदेश देंगे हजारों कदम

13 से 60 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी ले सकेंगे हिस्सा, विजेताओं को मिलेंगे नगद पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण-पत्र

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● जिले में नशा मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से धार पुलिस द्वारा 'Say No To Drugs - नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान के तहत 26 जुलाई (रविवार) को जिला पुलिस लाइन परिसर से मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जिले के 13 से 60 वर्ष तक के सभी नागरिक भाग ले सकेंगे।

प्रतिभागियों की सुविधा एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। इसमें हाफ मैराथन (4 किलोमीटर) तथा फुल मैराथन (8 किलोमीटर) शामिल हैं। प्रतिभागी अपनी आयु एवं सुविधा के अनुसार किसी भी श्रेणी में भाग ले सकेंगे। धार पुलिस द्वारा सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को निःशुल्क मैराथन टी-शर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद प्रतिभागी जिला पुलिस लाइन स्थित डीआरपी लाइन क्रिकेट ग्राउंड के काउंटर से अपनी टी-शर्ट प्राप्त कर सकेंगे।

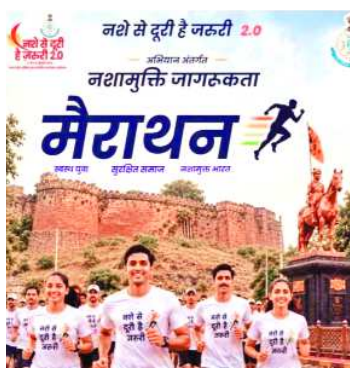

मैराथन के समापन पर दोनों रूट की पुरुष एवं महिला श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। आयोजन 26 जुलाई 2026 (रविवार) को जिला पुलिस लाइन, धार में होगा। प्रतिभागियों की रिपोर्टिंग सुबह 7 बजे से होगी, जबकि मैराथन सुबह 7:30 बजे प्रारंभ होगी। धार पुलिस ने जिले के नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में भाग लेने की अपील करते हुए कहा है कि नशामुक्त समाज के निर्माण के इस जन-जागरूकता अभियान को सफल बनाने में सभी अपना योगदान दें।

शादी के गहने चोरी का आरोप, 3.65 लाख का माल बरामद

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ●

मूंदी पुलिस ने शादी के गहने और नकदी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए नागपुर (महाराष्ट्र) से एक युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.15 लाख रुपए नकद, करीब 2.50 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की है। बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 3.65 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार, तालाब मोहल्ला, मूंदी निवासी ऋषभ पिता विनोद राठौर ने 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी मौसी की बेटी अम्बिका उर्फ खुशी शादी के लिए रखे गए सोने के गहने और 1.80 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गई है। शिकायत के आधार पर थाना मूंदी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम नागपुर (महाराष्ट्र) पहुंची और कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

यह आरोपी हुए गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में अम्बिका उर्फ खुशी (18), रमजान शेख (24) और मुकेश उर्फ भैरव (22) शामिल हैं। तीनों पंधाना थाना क्षेत्र के बोरगांव बुजुर्ग के निवासी हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2.50 लाख रुपए के सोने के जेवर, 1.15 लाख रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद मशरूका की कुल कीमत करीब 3.65 लाख रुपए आंकी गई है।

पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले के खुलासे में झड़ू राजेंद्र नरवरिया, इंस्पेक्टर उमेश लाखरे, बोरगांव चौकी प्रभारी अविनाश भोपले, एएसआई फिरोज खान, आरक्षक नरेंद्र यादव और दिनेश सिसोदे की भूमिका रही।

जिम्बाब्वे दौरे को युवा टीम इंडिया तैयार, श्रेयस संभालेंगे कप्तानी, 23 से होगा सीरीज का आगाज

नई दिल्ली (एजेंसी) ● भारतीय टीम का नया मिशन अब शुरू होने को है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 और उसके बाद वनडे सीरीज में मुंह की खाने के बाद टीम इंडिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से होने जा रहा है। सीरीज के दौरान तीन मैच खेले जाएंगे, जिसमें कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर से श्रेयस अय्यर संभालेंगे, जो इतने दिन बाद भी पहली जीत की तलाश में हैं। टीम इंडिया इस वक्त जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है और अपनी तैयारी कर रही है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों की

सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई यानी गुरुवार को हरारे में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया का ऐलान काफी पहले ही कर दिया गया था। सीरीज का दूसरा मैच 25 जुलाई दिन शनिवार को होगा, तीसरा और आखिरी मैच 26 जुलाई दिन रविवार को खेला जाएगा। तीनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेले जाएंगे। सभी की नजर इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी और युवा वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर रहेगी। जिन्होंने हाल ही में अपना डेब्यू किया है, लेकिन अब तक अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं।

कुलदीप को अवसर नहीं मिलने का कारण शुभमन ने बताया

लंदन (एजेंसी) ● भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में एक भी मुकाबला खेलने का अवसर नहीं मिला। यहां तक कि लॉर्ड्स में खेले गए निर्णायक तीसरे एकदिवसीय में भी

उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली जबकि मैच के दौरान स्पिनरों को काफी सहायता मिली। इसी को लेकर कप्तान शुभमन गिल ने सफाई दी है शुभमन ने कहा कि शुरुआती दोनों एकदिवसीय में पिच से स्पिनरों को अधिक सहायता नहीं मिली। इसी कारण टीम प्रबंधन ने अतिरिक्त स्पिनर खिलाने की जगह पर तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया था। गिल ने कहा, पहले दो मैचों में हमने देखा कि पिच स्पिनरों के लिए ज्यादा सहायक नहीं थी। जब स्पिनर गेंदबाजी करते थे तो हमें रक्षात्मक फील्ड लगानी पड़ती थी, जबकि तेज गेंदबाजों के साथ विकेट मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही थी। इसी कारण से कुलदीप को टीम में जगह नहीं मिली। लॉर्ड्स में हुए मैच को लेकर शुभकन ने कहा कि मुकाबला आगे बढ़ने के साथ विकेट धीमा हो गया और बाद में स्पिन गेंदबाजी ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती थी। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा, अब देखें तो लगता है कि स्पिनर बेहतर विकल्प हो सकता था। जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तब ऐसा नहीं लग रहा था कि विकेट इतना धीमा होगा, लेकिन दूसरी पारी में पिच काफी धीमी हो गई। भारत की यह रणनीति मैदान पर सफल नहीं रही। टीम के चारों तेज गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए और महत्वपूर्ण विकेट लेने में नाकाम रहे।कुलदीप ने अपना पिछला एकदिवसय जून में अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेला था, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला थ। कुलदीप यादव का इंग्लैंड में रिकॉर्ड काफी सम्मानजनक रहा है। उन्होंने यहां अब तक 10 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 15 विकेट लिए हैं।

क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाना है तो छोटी टीमों को बड़ी टीमों से मुकाबलों का अवसर मिले : अश्विन

मुंबई (एजेंसी) ● भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाना है तो उभरती हुई टीमों को नियमित अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने का अवसर मिले। अश्विन के अनुसार हाल में आईसीसी ने जिस प्रकार से टीमों की संख्या बढ़ाई है उसका तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि इन छोटी टीमों को बड़ी टीमों के खिलाफ पर्याप्त अवसर न मिले। आईसीसी ने कुछ समय पहले ही एकदिवसीय विश्व कप और 2028 के टी-20 विश्व कप के प्रारूप में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। नए प्रारूप के तहत साल 2027 के एकदिवसीय विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और प्रतियोगिता को तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। जिससे मुकाबलों की संख्या और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी। वहीं, 2028 के टी-20 विश्व कप में भी दूसरे चरण में अधिक टीमों को शामिल करने की योजना है, ताकि टूर्नामेंट और अधिक रोमांचक बन सके। अश्विन का मानना है कि प्रतिस्पर्धा के लिहाज से यह कदम सही दिशा में है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, यदि अंतिम लक्ष्य क्रिकेट का वैश्विक विस्तार करना है, तो उभरते देशों के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी।

रिश्तों में दूरी आती है, तो प्यार की कीमत बढ़ जाती है : शहनाज गिल

मुंबई (एजेंसी) ● पंजाबी फिल्म 'इश्कनामा' को लेकर अभिनेत्री शहनाज गिल चर्चा में हैं। शहनाज ने फिल्म की रिलीज से पहले प्यार और रिश्तों की जटिलताओं पर अपने विचारों को खुलकर साझा किया। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जब दो लोगों के बीच भौगोलिक या भावनात्मक दूरी आती है, तो कई बार प्यार की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है। यह दूरी सामने वाले की उपस्थिति की कमी शिद्दत से महसूस होने लगती है। हालांकि, दूरी के साथ ही रिश्तों में कुछ अनिश्चितताएं और शक भी पैदा हो सकते हैं, जो संबंधों की नींव को हिला सकते हैं। जब

शहनाज से पूछा कि क्या दूरी प्यार को मजबूत बनाती है या धीरे-धीरे रिश्ते को कमजोर कर देती है, तो इस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, जब रिश्तों में दूरी आती है, तो प्यार की कीमत बढ़ जाती है। यह सच है कि दूरी अक्सर दिलों को और करीब ला देती है, क्योंकि इंसान को सामने वाले की अहमियत और अधिक महसूस होने लगती है। लेकिन हां... यह भी सच है कि आपको यह नहीं पता होता कि दूसरा व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में क्या कर रहा है। इसलिए दूरी के साथ शक और अनिश्चितता भी बढ़ सकती है, जो रिश्ते के लिए एक चुनौती बन जाती है। शहनाज ने आगे कहा कि किसी भी रिश्ते में प्यार और भरोसा दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं।

रियलिटी शो दिखाते है कलाकारों का असली चेहरा : ईशा सिंह

मुंबई (एजेंसी) ●अभिनेत्री ईशा सिंह अपनी उपस्थिति के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो और अभिनय की दुनिया के बीच के मूलभूत अंतरों पर उन्होंने अपनी राय साझा की है। अभिनेत्री ईशा का मानना है कि रियलिटी शो दर्शकों को किसी कलाकार के असली स्वभाव और व्यक्तित्व को करीब से जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। एक विशेष साक्षात्कार में ईशा सिंह से जब पूछा गया कि क्या रियलिटी शो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं, इस पर उन्होंने अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा, मुझे यह ठीक-ठीक नहीं पता कि इससे किसी कलाकार की लोकप्रियता कितनी बढ़ती है, लेकिन यह सच है कि दर्शकों को अपने पसंदीदा सितारों की निजी जिंदगी और उनकी असल पर्सनैलिटी के बारे में जानने में हमेशा गहरी दिलचस्पी रहती है।

उज्जैन संभाग

स्कूलों की शिफ्टिंग का विरोध, छात्राएं बोलीं- पढ़ाई और सुरक्षा पर पड़ेगा असर

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● शासकीय बालिका विद्यालयों को दाऊदखेड़ी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ छात्राएं, अभिभावक और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को सभी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को शहर से दूर ले जाने से छात्राओं की सुरक्षा, पढ़ाई और नियमित उपस्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। प्रशासन ने सभी आपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। शासकीय बालिका विद्यालयों को दाऊदखेड़ी स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को 10 स्कूलों की 2698 छात्र-छात्राओं के भविष्य के लिए अभिभावक और शिक्षक छात्र-छात्राएं रैली के रूप में प्रशासनिक संकुल पहुंचे। विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने एसडीएम एल.एन. गर्ग को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि विद्यालयों को उनके वर्तमान स्थान से नहीं हटाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर के अलग-अलग इलाकों और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में छात्राएं इन विद्यालयों में पढ़ने आती हैं। यदि स्कूलों को दाऊदखेड़ी शिफ्ट किया गया, तो

नौबत आ।

उन्हें रोज कई किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। इससे समय, परिवहन और सुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ेगा। आठवीं कक्षा की छात्रा काजल माली ने कहा कि स्कूल शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें शहर से दूर ले जाना छात्राओं के हित में नहीं है। उनका कहना था कि लंबी दूरी के कारण कई छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने तक की सकती है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस फैसले का विरोध अप्रैल महीने से लगातार किया जा रहा है। उनका तर्क है कि शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यालयों की दूरी और छात्राओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने प्रशासन से इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

युवक ज्ञापन की माला पहन जनसुनवाई पहुंचा

दैनिक इंदौर संकेत

नागदा। ● मंगलवार को जनसुनवाई में एक युवक अपने पुराने ज्ञापनों की माला पहनकर प्रशासन के समक्ष पहुंचा। उसने ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता देव सिंह गुर्जर ने बताया कि वह पिछले पांच वर्षों से ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा फंड के तहत किए गए कार्यों, खर्च की गई राशि और लाभार्थियों की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को कई ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अब तक कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है। गुर्जर ने कहा कि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने से उन्हें इतने आवेदन जमा करने पड़े कि उनकी माला बनाकर पहनने की नौबत आ गई। उन्होंने इस माला को प्रशासनिक निष्क्रियता और जनता की अनसुनी आवाज का प्रतीक बताया।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा मद के तहत विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने तथा उन पर खर्च की गई राशि की जानकारी सार्वजनिक की जाती रही है। हालांकि, इन कार्यों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सत्यापन आवश्यक है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि जनता के हित और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच जरूरी है कि ष्ट्रस्क निधि का उपयोग वास्तव में निर्धारित उद्देश्यों के लिए हुआ है या नहीं।

देव सिंह गुर्जर ने प्रशासन से मांग की है कि पिछले पांच वर्षों में ष्ट्रस्क के तहत किए गए सभी कार्यों की सूची सार्वजनिक की जाए। साथ ही, प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत और वास्तविक खर्च की गई राशि का मिलान किया जाए, कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और लाभार्थियों को वास्तविक लाभ मिला है या नहीं, इसकी भी जांच की जाए।

पुलिसकर्मी के बेटे पर 14.50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● महिला ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। महिला ने आरोप लगाया है कि एक पुलिसकर्मी के बेटे ने उससे और उसके बेटे से कुल 14.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। महिला का कहना है कि पैसे मांगने पर पुलिसकर्मी पिता ने उन्हें धमकाया और झूठे मामले में फंसाने की चेतावनी दी।

बिहारीगंज निवासी शिकायतकर्ता शारदा मौर्य ने अपने आवेदन में बताया कि आरोपी युवक उनके बेटे का मित्र था और वर्षों से उनके परिवार के सदस्य की तरह घर आता-जाता था। विश्वास में लेकर उसने विभिन्न बहानों से पैसे उधार लिए। इनमें पिता के इलाज, रजिस्ट्री छुड़ाने और कपड़े की दुकान में माल भरने जैसे कारण शामिल थे। शारदा मौर्य के अनुसार, उन्होंने स्वयं लगभग 13 लाख रुपए दिए, जबकि उनके बेटे ने दो किश्तों में 1.50 लाख रुपए दिए। इस प्रकार कुल 14.50 लाख रुपए की राशि नकद और ऑनलाइन माध्यम से दी गई। महिला का दावा है कि पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह राशि वापस नहीं की गई है। जब परिवार पैसे मांगने युवक के घर गया, तो उसके पिता ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया। युवक के पिता सोनकच्छ थाने में पदस्थ बताए गए हैं। उन्होंने अपने पद और प्रभाव का हवाला देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया और झूठे मामले में फंसाने तथा जेल भेजने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में डीएसपी बबीता बामनिया ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों को स्कूल भेजा, महिला ने लगाई फांसी

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● शहर के शुक्रवारिया हाट क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक 38 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला की पहचान रिंकी पति मनोज पडियार (38) के रूप में हुई है। घटना के दिन सुबह उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए ऑटो में बैठाया था। उस समय उनके पति मनोज सुबह की सैर पर गए हुए थे। पार्षद बाली घोषी ने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रिंकी पूजा करने मंदिर गईं और फिर घर लौट आईं। कुछ देर बाद जब पति मनोज पडियार घर पहुंचे, तो उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आशंका होने पर मनोज ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो रिंकी फंदे पर लटकी हुई थीं। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि, आत्महत्या के स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आए हैं और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। पार्षद घोषी भी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि महिला ने बच्चों को स्कूल भेजने और मंदिर जाने के बाद फांसी लगाई।

रतलाम-नागदा तीसरी-चौथी रेल लाइन का सर्वे शुरू, 1018 करोड़ की परियोजना से किसानों को लाभ

दैनिक इंदौर संकेत

नागदा। ● रतलाम-नागदा के बीच प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का नागदा क्षेत्र में सर्वे शुरू हो गया है। करीब 1,018 करोड़ रुपए की इस परियोजना से रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन संभावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और निवेशकों की चिंता भी बढ़ गई है। दो पूर्व विधायकों ने किसानों के समर्थन में परियोजना का विरोध करने की घोषणा की है।

दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर के तहत स्वीकृत 41 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,018 करोड़ रुपए है। निर्माण एजेंसी ने उज्जैन-जावरा टू-लेन मार्ग के पास सर्वे और मिट्टी परीक्षण शुरू कर दिया है। रेलवे का लक्ष्य अगले तीन से चार वर्षों में परियोजना पूरी करना है।

वर्तमान में रतलाम-नागदा के बीच दो रेल लाइनें होने से ट्रेनों का दबाव रहता है। तीसरी और चौथी लाइन बनने से रेल संचालन तेज और सुगम होगा। रेलवे के अनुसार, भविष्य में अधिकांश मालगाड़ियां नई लाइनों से संचालित होंगी, जिससे मुख्य रेलवे यार्ड पर भार कम होगा। सर्वे शुरू होने के बाद किसानों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं, बायपास क्षेत्र में निवेश करने वाले कॉलोनाइजर और भूमि मालिक भी प्रस्तावित रेल लाइन को लेकर असमंजस में हैं। जानकारी के अनुसार, नई रेल लाइन उज्जैन-जावरा मार्ग से करीब 135 मीटर दूरी पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना के अनुसार नई रेल लाइन उमरनी फाटक से आगे बढ़ते हुए चामुंडा माता मंदिर के पास चंबल नदी पर नए रेल पुल से गुजरेगी। इसके बाद यह जूना नागदा, बेरछा रोड, रतन्याखेड़ी रोड और महिदपुर रोड होते हुए बनबनी क्षेत्र में मौजूदा रेल मार्ग से जुड़ेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठे

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकभवन का घेराव किया गया। पटवारी ने कहा लोकतंत्र की आवाज को दबाने के हर प्रयास के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस विधायकों के साथ छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा परिसर में मौजूद मुख्यमंत्री चैंबर के बाहर धरने पर बैठे। मंत्री विजयवर्गीय ने पहुंचकर सिंघार से धरना खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। इधर, पुलिस ने रात सवा 11 बजे जबरन धरना खत्म कराकर पटवारी को हिरासत में ले लिया।

विजयवर्गीय की भुट्टा पार्टी...

भोपाल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में सभी विधायकों, नेताओं एवं पत्रकारों को भुट्टा पार्टी दी। इसमें मौजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य।

बीजेपी नेता की सीलिंग जमीन केस में कॉलोनी सेल को झटका, संभागायुक्त कोर्ट से स्टे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जिराती के करीबी और पूर्व पार्षद पति नीलेश चौधरी के परिवार की 200 करोड़ की स्वास्तिक ग्रेंड कॉलोनी की विकास मंजूरी में नया मोड़ आ गया। संभागायुक्त इंदौर की कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

जमीन सीलिंग केस-पूर्व विधायक जीतू जिराती के करीबी बीजेपी नेता नीलेश चौधरी और उनके परिवार की हातोद के सोनगीर की 17 हेक्टेयर जमीन में सीलिंग का पेंच फंसने के बाद नया मोड़ आ गया है। इस केस में कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर अपर कलेक्टर कॉलोनी सेल रिंकेश वैश्य ने विकास मंजूरी रद्द कर दी थी। द सूत्र ने पूरे मामले का खुलासा किया था। अब इसमें नया पेंच आ गया है।

हाईकोर्ट और संभागायुक्त में लगी थी केविएट-विकास मंजूरी रद्द होने के बाद से ही इसमें भूस्वामी चौधरी परिवार और डेवलपर्स शरद गुप्ता व अन्य स्टे लेने में जुट गए थे। वहीं कलेक्टर के आदेश पर कॉलोनी सेल ने संभागायुक्त कार्यालय में और हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी थी।

संभागायुक्त कोर्ट में आधे घंटे चली बहस-इस मामले में मंगलवार को संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की कोर्ट में आधे घंटे बहस चली। कॉलोनाइजर की ओर से पूर्व एडिशनल एजी विश्वजीत जोशी थे तो वहीं शासन की ओर से खुद कॉलोनी सेल की प्रभारी डिप्टी कलेक्टर रोशनी पाटीदार थी। इसमें लंबी बहस हुई इसके बाद देर शाम इसमें आदेश हुए। भू स्वामी की ओर से बताया गया कि यह राजस्व कोर्ट के आदेश से सीलिंग मुक्त हो गई थी लेकिन राजस्व रिकार्ड नहीं होना प्रशासन की चूक है।

कलेक्टर के आदेश पर लगाई रोक-इस मामले में संभागायुक्त कोर्ट ने फिलहाल कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस मामले में कॉलोनी सेल से पूरी फाइल और रिकार्ड बुलाए गए हैं। साथ ही इसमें अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। इसमें अंतिम फैसला दिया जाएगा।

बिना पढ़ाए परीक्षा, नंबरों की जगह रिजल्ट में स्टार असिस्टेंट प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एमएड (सत्र 2025-2027) के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ तो छात्र हक्के-बक्के रह गए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन (विषय कोड 626) विषय में नंबर या ग्रेड देने के बजाय विश्वविद्यालय ने रिजल्ट तालिका में सीधे स्टार (*) चिन्ह लगा दिया। पूरे सत्र कक्षाएं न लेने, जबरन परीक्षा करवाने और अब तीसरे सेमेस्टर में भी पढ़ाई न करवाने से प्रताड़ित होकर छात्र मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को शिकायत की।

कुलपति ने बिना मिले लौटाया: छात्रों ने शिकायत पत्र में बताया कि समस्या के समाधान के लिए जब वे विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलगुरु से मिलने आरएनटी मार्ग स्थित कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें लगभग 4 घंटे तक बाहर बिठाकर रखा गया। घंटों इंतजार के बाद भी कुलपति उनसे नहीं मिले और सांत्वना देकर विभाग वापस भेज दिया गया।

नौकरी पर आएगा संकट, कुछ छात्र हैं नेट पास-विभाग की ओर से जारी टेंटेटिव रिजल्ट की प्रति के अनुसार विषय कोड 626 के कॉलम में छात्रों के अंक ग्रेड की जगह मात्र बना दिया गया है। छात्रों का कहना हैं कि उनमें से कुछ विद्यार्थी नेट परीक्षा भी पास कर चुके हैं। यदि विश्वविद्यालय की इस लापरवाही और आंतरिक खींचतान के कारण उनका रिजल्ट प्रभावित होता है या उन्हें अनुत्तीर्ण किया जाता है, तो उनकी नौकरियों पर संकट आ जाएगा।

आवाज उठाई तो दी फेल करने की धमकी

कलेक्टर को सौंपे गए पत्र के अनुसार स्कूल ऑफ एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. परीणिता रत्नपारखी पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है प्रोफेसर ने समय-सारणी के अनुसार कक्षाएं नहीं ली, वहीं जबरन परीक्षा देने का दबाव बनाया गया। जब छात्रों ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया, दरवाजे पर पैर लगाकर रोका गया और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई। लगातार मानसिक तनाव के कारण 1 छात्र सत्र के बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले गए।

प्रमोशन में आरक्षण पर बहस फिर टली पहले सुना जाएगा ओबीसी आरक्षण मामला

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई टल गई है। पहले ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई पूरी होगी। महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि फैसला विपरीत आने पर सभी प्रमोशन वापस लिए जाएंगे। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में टल गई है। पहले ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई पूरी होगी। सरकार हजारों पदों पर पहले ही प्रमोशन दे चुकी है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को फैसले के पालन का भरोसा दिया।

अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को तय हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में आज बड़ा मोड़ आया। इस मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अब यह सुनवाई ओबीसी आरक्षण मामले की बहस पूरी होने के बाद होगी। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 3 अगस्त तय की है।

क्यों टली सुनवाई- यह मामला एमपी हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की स्पेशल डिविजनल बेंच में चल रहा है। आज इसी दिन दोपहर 2:30 बजे ओबीसी आरक्षण मामले की भी सुनवाई तय थी। यह सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में होनी थी। कोर्ट के सामने बताया गया कि दोनों मामलों में जस्टिस विनय सराफ के साथ ही सरकार और प्रतिवादियों के वकील भी एक जैसे हैं। इसी वजह से कोर्ट ने तय किया कि पहले ओबीसी आरक्षण मामला सुना जाएगा।

सामान्य वर्ग के वकील ने रखी बड़ी बात - सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग की तरफ से अधिवक्ता मनोज शर्मा ने अहम बात कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि सरकार हजारों की संख्या में प्रमोशन दे रही है। उनका कहना था कि अगर कोर्ट का फैसला प्रमोशन के खिलाफ आया तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में प्रमोशन वापस लेना आसान काम नहीं होगा। सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

पशु मुक्त देपालपुर में फिर दिखने लगी गाये

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

नगर परिषद देपालपुर को स्वच्छ बनाने के लिए इंदौर नगर निगम ने गोद लिया था जिसका असर पिछले 1 साल में नगर परिषद में देखने को मिला। सबसे पहली प्राथमिकता देपालपुर नगर कचरे से मुक्त हो दूसरा सबसे बड़ा विषय था। आवारा पशुओं का जिसको लेकर नगर निगम इंदौर के कर्मचारी और देपालपुर के कर्मचारियों ने मिलकर आवारा पशुओं को रेशम केंद्र गौशाला में छोड़ा गया। नगर में पशु दिखना बंद हो गए लगातार यह अभियान देपालपुर नगर में 8 दिन तक चलता रहा लेकिन वर्तमान स्थिति में नगर में लगातार आवारा पशु देखने को मिल रहे हैं।

गाये सड़क किनारे बड़े-बड़े वाहनों के समीप खड़ी रहती। दुकानों के बाहर लगे चद्दर सेट पर गाये बैठ जाती है। सबसे बड़ा सवाल है पशु मुक्त नगर में गाये कहा से आ रही कौन इन गायों को नगर में छोड़ कर जा रहा क्या यह गाये किसी की निजी तो नहीं है। इसका पता लगाना नगर परिषद को अनिवार्य है। धीरे-धीरे गायों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देपालपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा पशु हाट बाजार लगता है। हो सकता है जो गाड़ियां नगर में आ रही है वह इन गायों को यहां छोड़कर चली जाती है। बाहर से आ रही गाड़ियों को जांच करने की आवश्यकता है।

नगर में गायों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर परिषद को कठोर कदम उठाने होंगे इतना ही नहीं निजी गौ सेवकों की गाये पकड़कर कार्यवाही करना होगी। नगर परिषद देपालपुर लगातार स्वच्छता के लिए कार्य कर रही इसके कई उदाहरण नगर में देखने को मिले हैं।

इंदौर में जल आपूर्ति विस्तार की तैयारी तेज

30 नई पानी की टंकियों की डिजाइन आईआईटी खड़गपुर भेजी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में बढ़ती आबादी और नए शामिल क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस चरण के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में 30 से अधिक नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। टंकियों की ड्राइंग और डिजाइन तैयार कर परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए आईआईटी खड़गपुर भेजी गई है।

नगर निगम जलकार्य समिति के प्रभारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि नए और 29 गांवों वाले क्षेत्रों में बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टंकियों के स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार डिजाइन का परीक्षण किया जा रहा है। आईआईटी खड़गपुर से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव भोपाल भेजा जाएगा और अंतिम मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। नर्मदा परियोजना के

चौथे चरण में करीब 2700 करोड़ रुपये की लागत से चार पैकेजों में कार्य किए जाएंगे। इसके तहत कई इलाकों में नई नर्मदा जलापूर्ति पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। जिन क्षेत्रों तक अभी नर्मदा जल की पहुंच नहीं है, वहां सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। नर्मदा परियोजना और नगर निगम के विभिन्न जोन के इंजीनियरों की टीमें अलग-अलग वार्डों में जाकर सर्वे कर रही हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि कई क्षेत्रों का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि शेष क्षेत्रों में कार्य जारी है। हालांकि अधिकांश टंकियों के लिए स्थान तय हो चुके हैं, लेकिन सात से आठ स्थानों पर भूमि विवाद के कारण मामला अटका हुआ है। इन विवादों के समाधान के बाद वहां भी टंकियों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नगर निगम का दावा है कि चौथे चरण के कार्य पूरे होने के बाद शहर के नए विकसित क्षेत्रों और ग्रामीण सीमा से जुड़े इलाकों में भी नर्मदा जल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

बिना प्लानिंग के सड़क की खुदाई

इंदौर। जंजीर वाला चौराहे से लेकर अटल द्वार बनने वाली नई सड़क के लिए, बगैर किसी सूचना के जंजीर वाला चौराहा के आगे खुदाइ कर दी हे,पुरा रोड पुरी चौडाई मे खोदा गया है, पूरा ट्रैफिक जो अटल द्वार और झांझर की बीच चलता था वह बाधित हो गया है। यह बगैर किसी प्लानिंग के ,कोई योजना के काम करने का नतीजा है और पूरा जंजीरवाला चौराहा इससे जाम की स्थिति में आ गया है । निश्चित यह एक अपने आप में गैर जिम्मेदारना काम,जो बगैर योजना की किया गया कार्य है।

मेट्रो ट्रेन के डिपो की ओपन लैंड का कम होगा संपत्तिकर

तालाब रोड और रेल लाइन सहित अन्य क्षेत्र पर लगा दिया था टैक्स

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● संपत्तिकर वसूली को लेकर नगर निगम राजस्व विभाग ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को करीब 8.5 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया था। गांधी नगर में मेट्रो डिपो और 17 स्टेशन का संपत्तिकर बिल भेजा गया था। इस पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अफसरों ने आपत्ति ली, क्योंकि गांधी नगर में मेट्रो डिपो की ओपन लैंड पर जो टैक्स लगाया गया था, उसमें तालाब, रोड, रेल लाइन और अन्य वह क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया था, जिस पर संपत्तिकर लगता ही नहीं। अब ओपन लैंड में से इन स्थानों का संपत्तिकर कम किया जाएगा। इसे लेकर राजस्व विभाग के अमले ने कल नपती कर ली है, जिसकी रिपोर्ट आज राजस्व विभाग के अपर आयुक्त को सौपी जाएगी। मेट्रो रेल की जिन संपत्तियों पर टैक्स लगना है, उसे देने की सहमति मेट्रो के अफसरों ने दी है।

गांधीनगर में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा डिपो बनाया है, जहां से प्रशासनिक कामों का संचालन होता है। इसके अलावा करीब 17 स्टेशन भी अलग-अलग स्थानों पर बन गए है। निगम के राजस्व विभाग ने गांधीनगर के डिपो की ओपन लैंड के साथ बने स्ट्रक्चर व स्टेशनों की नपती करने के बाद करीब 8.5 करोड़ रुपए का संपत्तिकर बिल भेज दिया था। इस पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अफसरों ने आपत्ति लेने के साथ कहा कि डिपो में टैक्स की गणना सही तरीके से नहीं की गई है, क्योंकि ओपन लैंड में उन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया, जिस पर टैक्स लगाता ही नहीं।

इधर, मेट्रो रेल अफसरों की आपत्ति के बाद राजस्व विभाग के अपर आयुक्त आकाश सिंह ने कल मुख्यालय एआरओ अजीम खान को अपनी टीम के साथ मौके पर नपती करने के लिए भेजा। राजस्व अमले ने नपती कर ली, जिसकी रिपोर्ट आज अपर आयुक्त सिंह को दी जाएगी। मामले में अपर आयुक्त सिंह का कहना है कि गांधी नगर डीपो की ओपन लैंड का संपत्तिकर कम हो सकता है, क्योंकि वहां बनी बिल्डिंग का तो संपत्तिकर लगेगा, लेकिन ओपन लैंड में शामिल तालाब, रोड और रेल पटरी सहित जिन क्षेत्रों पर टैक्स नहीं लगता, उसे फिर से गणना कर हटाया जाएगा। बिजली की ग्रिड वाले एरिया का टैक्स न लेने का मेट्रो के अफसरों ने कहा है, मगर निगम बिजली के ग्रिड एरिया का टैक्स लेता है इसलिए मेट्रो से भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओपन लैंड से एरिया घटाने और बने हुए स्ट्रक्चर का टैक्स लेने की सहमति बन गई है। कल हुई नपती की आज रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से संपत्तिकर की गणना कर मेट्रो को बिल जारी किया जाएगा। जितना टैक्स बनेगा वह मेट्रो को अदा करना पड़ेगा।

राजस्व विभाग अमले ने मौके पर की नपती, आज देंगे रिपोर्ट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : अक्षय तिवारी द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।